ICAR-भारतीय सोयाबीन अनुसन्धान संस्थान
खंडवा रोड, इंदौर -452001

F. No. Press & Publicity/Soya Mahakumbh/2022/5 Date: 29.05.2022

आईसीएआर-भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, सोयाबीन अनुसंधान एवं विकास सोसायटी, सोलिडारिडाड, भोपाल और सोपा इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में 29-31 मई, 2022 के दौरान आयोजित किये जा रहे "सोया महाकुम्भ" का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के ऑडिटोरियम में आज उदघाटन हुआ. कार्यक्रम में पहले दिन इसमें सोयाबीन उत्पादक, वैज्ञानिक, विकास विभागों के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 2500 लोगों ने भाग लिया. इसके उदघाटन समारोह में माननीय श्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री; श्री कमल पटेल, कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश; डॉ त्रिलोचन महापात्रा, सचिव डेयर और महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, माननीय श्री शंकर लालवानी, इंदौर से सांसद, भाकृअनुप-आईआईएसआर निदेशक डॉ नीता खांडेकर और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया.

प्रारंभ में, भारतीय सोयाबीन अनुसन्धान संस्थान की कार्यवाह निदेशक डॉ नीता खांडेकर ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और विभिन्न विधाओं का उपयोग करते हुए अनुसंधान जनित तकनीकियो एवं नवीनतम पद्धतियों को किसानों तक ले जाने के लिए संस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर डॉ. महापात्रा ने कहा कि सोयाबीन की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पिछले कुछ दशकों से लगभग 1 टन प्रति हेक्टेयर है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिये, विस्तार कर्मियों, किसानों, इनपुट डीलरों और सहायक सेवाओं में शामिल अन्य लोगों के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि सोयाबीन की नई किस्मों का गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में वृद्धि से ही सोयाबीन की उत्पादकता 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि 14,326 क्विंटल के ब्रीडर बीज उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है जिससे आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम में तेजी आएगी। उन्होंने विशेष रूप कहाँ कि सोयाबीन बीज स्थानापन्न दर के साथ साथ किस्मों की विविधता भी आवश्यक हैं. डॉ महापात्रा ने यह भी आशा व्यक्त की कि मध्य भारत के किसानों ने लगभग 2-3 टन / हेक्टेयर की उपज सीमा हासिल कर ली है जैसा कि फ्रंटलाइन प्रदर्शनों में परिलक्षित होता है। इसलिए, उन्होंने कहा कि किसानों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए कृषि प्रयास किये जाने चाहिए।

इस अवसर पर इंदौर के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री शंकर लालवानी ने अपने संक्षिप्त संबोधन में बताया कि भारत सरकार ने उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि नहीं होने दी, विशेष रूप से यूरिया, जो पौधों की वृद्धि के लिए एक प्रमुख तत्व है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़, छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

इसी प्रकार विशिष्ठ अतिथि, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने अपने संबोधन में बताया कि मध्यप्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार ने किसान केंद्रित नीतियां बनाई हैं. उन्होंने कहा कि एमएसपी के माध्यम से खरीद की अधिकतम सीमा को हटा दिया गया है जिससे राज्य के किसानों को लाभ हुआ है. उन्होंने फसल बीमा योजना पर प्रकाश डाला, जिससे पिछले दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के किसानों को 17,000 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। उनके अनुसार, राज्य सरकार ने तीसरे सीजन की फसल यानी ग्रीष्म मूंग को बढ़ावा देने की योजना बनाई है, जिससे राज्य के किसानों की आय में भी योगदान होगा।

कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा संस्थान की "ईको फ्रेंडली सोया कटोरी" , सोयाबीन उत्पादकता पर वृद्धि के लिए तकनिकी बुलेटिन तथा 3s1Y परियोजना के अंतर्गत "ISKA सीड" को लांच कर कृषकों को समर्पित किया.

समारोह के मुख्य अतिथि, माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, भारत सरकार श्री कैलाश चौधरी ने देश की अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से महामारी की स्थिति में कृषक समुदाय की कड़ी मेहनत और योगदान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कृषि के बजटीय आवंटन को बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ कर दिया है जो 2014 के बाद से रिकॉर्ड वृद्धि है। इसमें से 65,000 करोड़ रुपये किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ के रूप में दिए जाते हैं, जिससे लगभग 50 लाख करोड़ किसानों को लाभ होता है। उन्होंने आगे बताया कि केंद्र सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किसान की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार, छोटे और सीमांत किसानों को एक साथ आना चाहिए और अपनी उपज के उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण के लिए किसान उत्पादक संगठन (FPO) के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड के लिए लगभग 1 लाख करोड़ आवंटित किए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ-साथ मूल्यवर्धन के लिए प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा के लिए है। श्री चौधरी ने देश की विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त 164 सोयाबीन किस्मों के विकास में कृषि वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान बढ़ेगा।